the agricultural sector by the State Govts., the farmers do not realise the potential for energy savings through more energy efficient pump sets. The State Electricity Boards and the farmers are being educated on energy efficiency in the pumping systems. The Govt, of India has also given assistance to the State Electricity Boards and other organisations, for rectification of pump sets. The State Govts, are also being urged upon to levy agricultural tariff in order to encourage farmers to use energy efficient pump sets.

पकड़ा गया काला धन

88. **श्री नागमणि**:

श्री कनकसिं मोहनसिंह मंगरोला :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान अब तक पकड़े गए काले धन का ब्यौरा क्या, और

(ख) भविष्य में काले धन का पता लगाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी.चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान जनवरी, 1996 तक आयकर विभाग ने 35476.720 लाख रूपये की लेखाबाह्य परिसम्पत्तियों को पकड़ा है।

(ख) कानून के उपबंधों के अनुसार कर उपवंचकों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करना सरकार की घोषित नीति है । चूंकि कर अपवंचन रोकना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, अत: कर अपवंचन को रोकने के लिए सरकार तलाशी एंव अभिग्रहण, सर्वेक्षण एंव अभियोजना जैस विभिन्न कदम उठाती है।

विश्व बैंक द्वारा सहायता

89. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने राजस्थान में कृषि विकास परियोजना की सफलता से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में अन्य अनेक परियोजनाओं का वित्तपोषण करने का प्रस्ताव किया है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्सा है, और

(ग) इन राज्यों में विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषण के लिए प्रोत्साहित परियोजनाओं तथा उनके लिए प्रस्तावित सहायता की राशियां का बयौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा.देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र हेतु कृषि विकास परियोजनाओं का बैंक से संभावित वित्तपोषण किए जाने के लिए विश्व बैंक के साथ विचार-विमर्श चल रहा है । विश्व बैंक की सहायता की राशि सहित परियोजनाओं के ब्यौरों का पता परियोजनाओं को अंतिम रूप दिये जाने के बाद ही चलेगा।

Reservation of SC/ST in Nationalised Banks

90. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that reservation for SOST has been made upto Grade I officers only in all the nationalised banks in the country and there is no reservation in Grade II to IV of the bank officers;

(b) if so, the details and reasons therefor; and

(c) whether Government propose to make reservation in all the Grades of Banks Officers, if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBI PROSAD PAL): (a) Reservation for SC ST personnel exists in the case or promotion from clerical cadre to level of Scale I (JMGS-I) officers in public sector banks. Reservation does not exist in the case of promotion from Scale I onwards to next higher scales in cases involving promotion by selection method.

(b) and (c) The guidelines and policies framed by Government with regard to reservations for SCs & STs in Government service are adopted by public sector ' banks broadly in the same manner as it is